संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रीकरण

1724. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रीकरण हेतु कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रस्तावों पर अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या ऐसे प्रस्तावों पर कोई आम सहमति कायम हुई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (घ) भारत ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें अधिवेशन में "सुरक्षा परिषद् की सदस्यता में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और उसमें वृद्धि के प्रश्न" पर एक संकल्प सहप्रायोजित किया था। तत्पश्चात् 1993 में अपने 48वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मुक्त कार्यदल का गठन किया जो सुरक्षा परिषद् में सुधार और उसकी पुनर्संरचना पर विचार-विमर्श करता रहा है। भारत ने प्रस्ताव किया है कि सहमत मानदण्डों के आधार पर सुरक्षा परिषद् के स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की श्रेणी जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है, में विकासशील देशों को शामिल करने से सुरक्षा परिषद् के लोकतंत्रीकरण में योगदान मिलेगा। किसी भी मानदण्ड के आधार पर भारत सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनने के योग्य है। कई देश ऐसे व्यापक आधार पर स्थायी सदस्यों की संख्या का समर्थन करते हैं। जिसमें भारत भी शामिल होगा। कार्यदल में विचार-विमर्श चल रहा है। अभी सुरक्षा परिषद् के विस्तार के लिए उम्मीदवारों अथवा मानदण्ड पर कोई सहमति नहीं है।

Widening of National Highways

1725. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose to widen all National Highways to assist better road transport;

(b) whether it is a fact that sufficient by-pass roads are not on the National Highways between Vijayawada and Visakhapatnam; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) The development of National Highways including their widening is a continuous process. Widening of various NHs are taken up keeping in view the interse priority and the availability of resources.

(b) and (c) The By-pass around Eluru town between Vijayawada-Visakhapatnam section on N+5 was considered necessary for which an estimate has already been sanctioned.

Financial Crisis in U.N.

1726. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount in dollars and its equivalent in Indian Rupees, which the member-States owe to the U.N. and the country-wise break up of the defaulting member-States; and

(b) the step taken by U.N. for getting this amount in order to clear the outstanding amount due to India on account of the services rendered towards U.N. peace keeping force?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) The total amount outstanding to the United Nations as of July, 1996 stands at US $ 2.925 billion, equivalent to Rs. 102.375 billion approximately (at the current official rate of exchange of US $ 1.00= Rs. 35.00). Country-wise break up of the amounts owed to the UN by Member-States, as on 30 June, 1996, is annexed as statement (*see* below).

(b) The Government of India are making all efforts to obtain full reimbursement from the United Nations for the services rendered by it in the UN Peace-